GOVT OPTS FOR FRESH UPLINK AND DOWNLINK GUIDELINES

The new guidelines will propel India as a hub for uplinking

Govt has plans to simplify uplink and downlink guidelines and this will position India as a hub for uplinking by deregulating uplinking of satellite channels from the country.

The deregulation of uplinking channels will help broadcasters from neighbouring countries like Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Sri Lanka to uplink channels from India. India will become an uplinking hub if it is cost-competitive and satellite footprint covers a larger geography.

Currently the satellite capacity is not being adequately utilised due to the use of MPEG-2 video compressions format by the industry players including Prasar Bharati's DD Free Dish.Prasar Bharati offers 80 channels in MPEG-2 format. If it moves to MPEG-4 format then the number of channels can be increased to 160.

The process of migrating DD Free Dish customers to MPEG-4 has been a time-consuming process. Out of a total of 40 million only about 1 million have been converted to MPEG-4 and for the proper usage of the spectrum it would be better if they move from MPEG-2 to MPEG-4.

The government's decision to launch 200 educational channels will also require transponder capacity to reach the length and breadth of the country.

The communication and broadcasting is seeing a convergence and people are viewing content through mobiles and TV. The growth of TV industry in India has been static over the past two-three years. The number is about 200 million and it has been static whether it is the cable-connected homes or whether it is DTH services.

The government is also looking at direct-to-mobile broadcasting technology being developed by Prasar Bharati alongside IIT-Kanpur, The pilots have been successful and the technology is capable of providing 200 to 300 channels in rural areas over a local Wi-Fi network. ■

नयी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों को बनाने की तैयारी

नये दिशानिर्देश भारत को अपलिंकिंग हब के रूप में आगे बढ़ायेगा

सरकार की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों को सरल बनाने की योजना है और यह भारत को देश से सैटेलाइट चैनलों के अपलिंकिंग को डीरेगुलेट करके अपलिंकिंग के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। अपलिंकिंग चैनलों के नियंत्रण से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के प्रसारकों को भारत से चैनल को अपलिंक करने में मदद मिलेगी। भारत एक अपलिंकिंग हब बन जायेगा, बशर्ते कि यह लागत प्रतिस्पर्धी हो और सैटेलाइट फुटप्रिंट एक बड़े भूगोल को कवर करता है।

वर्तमान में प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश सहित उद्योग जगत के खिलाड़ियों द्वारा एमपीईजी–2 व्वीडियो कंप्रेशन प्रारूप के उपयोग के कारण सैटेलाइट क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रसार भारती एमपीईजी–2 प्रारूप में 80 चैनल प्रदान करता है। यदि यह एमपीईजी–4 प्रारूप में चला जाता है तो चैनलों की संख्या को 160 तक बढ़ाई जा सकती है।

डीडी फ्री डिश ग्राहकों को एमपीईजी–4 में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया रही है। कुल 40 मिलियन में से केवल 1 मिलियन को ही एमपीईजी–4 में परिवर्तित किया गया है और स्पेक्ट्रम के उचित उपयोग के लिए यह बेहतर होगा कि वे एमपीईजी–2 से एमपीजी–4 में चले जायें।

200 शैक्षिक चैनल शुरू करने के सरकार के फैसले के लिए देश के कोने–कोने तक पहुंचने के लिए ट्रांसपौंडर क्षमता की भी आवश्यकता होगी।

संचार और प्रसारण में कन्वर्जस को देखा जा रहा है और लोग मोबाइल और टीवी के माध्यम से सामग्री देख रहे हैं। भारत में टीवी उद्योग का विकास पिछले दो–तीन वर्षों में स्थिर रहा है। संख्या लगभग 200 मिलियन है और यह स्थिर रहा है चाहे वह केवल से जुड़े घर हों या डीटीएच सेवायें हों।

सरकार आईआईटी कानपुर के साथ प्रसार भारती द्वारा विकसित की जा रही डॉयरेक्ट–टू–मोबइल प्रसारण तकनीकी पर भी विचार कर रही है, पायलट सफल रहे हैं और तकनीक स्थानीय वाई–फाई नेटवर्क पर ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से 300 चैनल प्रदान करने में सक्षम है। ■